

जेवर एयरपोर्ट के पास बसेगी जैपनीज इलेक्ट्रॉनिक सिटी

100 एकड़ में अपनी यूनिटें लगाएंगी जापानी कंपनियां

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : जेवर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने के साथ यमुना एक्सप्रेस-वे अर्थोर्टी में विदेशी कंपनियां निवेश के लिए आने लगी हैं। इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनने के बाद दुनिया के बड़े शहरों के साथ बढ़ती कनेक्टिविटी को देखते हुए जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां यहाँ निवेश करना चाहती हैं। इसे देखते हुए योगी सरकार जेवर एयरपोर्ट के पास जैपनीज इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करेगी। यह शहर 100 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए जमीन की व्यवस्था सरकार जल्द करेगी। हाल ही में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने



जमीन की व्यवस्था जल्द करने के निर्देश भी दिए हैं।

जापानी कल्चर भी दिखेगा : जैपनीज इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जापान की कंपनियों के साथ वहाँ की संस्कृति के भी रंग दिखेंगे। इस शहर को विकसित करने के पीछे

सरकार की योजना है कि जितनी भी जापानी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं, उन्हें एक ही जगह पर जमीन मुहैया करवाई जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जापान की तरह ही कई और देशों की इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित की जाएगी। इनमें ताइवान भी शामिल हैं।

विकसित होगी एक और इलेक्ट्रॉनिक सिटी : जेवर एयरपोर्ट के पास 250 हेक्टेअर जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी। जल्द इसके लिए जमीन हैंडओवर की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल पार्क के लिए 350 हेक्टेअर भूमि का अर्जन किया जा चुका है। फिल्म सिटी के लिए

गंगा एक्सप्रेस-वे के भूमि अधिग्रहण के लिए हडको देगा 2,900 करोड़ रुपये का लोन

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया तेज हो, इसके लिए यूपीडा हडको से 2,900 करोड़ रुपये का लोन लेगा। मंगलवार को लोन के लिए यूपीडा की ओर से सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी और हडको के संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त) रत्न प्रकाश ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस रकम से एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन की खरीद होगी। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे के लिए 9,255 करोड़ रुपये से भूमि अधिग्रहण होना है। एक्सप्रेस-वे 12 जिलों की 30 तहसीलों से होकर गुजरेगा और कुल 7,438 हेक्टेअर जमीन खरीदी जानी है। 36,410 करोड़ रुपये का यह प्रॉजेक्ट 12 पैकेज में पूरा होगा।

1,000 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। औद्योगिक विकास विभाग

निवेश मित्र पोर्टल के जरिए जमीन आवंटन कर रहा है।